



Date : 18-12-2025

ओमान की खाड़ी

पाठ्यक्रम: जीएस2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध; जीएस1/ स्थान

समाचार में

- ईरान ने ओमान की खाड़ी में 60 लाख लीटर तस्करी के डीजल से लदे विदेशी तेल टैंकर को जब्त किया।



ओमान की खाड़ी के बारे में

- ओमान की खाड़ी अरब सागर की उत्तर-पश्चिमी शाखा है।
- यह हार्मुज जलडमरुमध्य के माध्यम से हिंद महासागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा बनाता है।
- हार्मुज जलडमरुमध्य के माध्यम से, यह फारस की खाड़ी तक पहुँच प्रदान करता है, जो इसे वैश्विक तेल और एलएनजी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
- ओमान की खाड़ी की उत्तरी सीमा ईरान, उत्तर-पूर्वी सीमा पाकिस्तान, दक्षिणी सीमा ओमान और पश्चिमी सीमा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मिलती है।

एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर

पाठ्यक्रम: जीएस3/रक्षा

समाचार में

- भारतीय सेना को तीन AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप मिली।

के बारे में

- इन अपाचे हेलीकॉप्टरों का अनुबंध 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 600 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत किया गया था।
- AH-64E अपाचे को दुनिया का सबसे उन्नत बहु-भूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है।
- यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर और हथियार प्रणालियों से लैस है, और सभी मौसम और इलाके की स्थितियों में काम करने में सक्षम है।

भारत में छात्र प्रवासन के बदलते पैटर्न

प्रसंग (Context)

- यह आकांक्षा और परिणाम के बीच, तथा अवसर और शोषण के बीच की खाइयों को उजागर करता है।

परिचय (Introduction)

भारत में छात्र प्रवासन की नवीनतम लहर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। यह अब केवल प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या पूर्णतः वित्तपोषित कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रही है। इसके बजाय, समकालीन प्रवासन मुख्यतः स्व-वित्तपोषित शिक्षा द्वारा संचालित है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार वैश्विक डिप्ली, बेहतर रोज़गार-योग्यता और ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता के बादे पर भारी निवेश कर रहे हैं।

- विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के आँकड़ों के अनुसार, 2023 में 70+ देशों में 13.2 लाख से अधिक भारतीय छात्र अध्ययनरत थे।
- यह संख्या 2024 में बढ़कर 13.35 लाख हो गई और 2025 तक 13.8 लाख तक पहुँचने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मिलकर भारतीय छात्रों के लगभग 40% गंतव्य हैं। अन्य प्रमुख गंतव्यों में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी शामिल हैं।
- इस प्रवृत्ति को संसदीय समिति on the Welfare of Indian Diaspora (2022) में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है।
- समिति छात्रों को भारत के विस्तारशील प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) की एक प्रमुख श्रेणी के रूप में पहचानती है।

विदेशी शिक्षा के 'लोकतंत्रीकरण' की सीमाएँ (Limits of the 'Democratisation' of Foreign Education)

दिखावटी समावेशन, गहरी असमानता: विदेशी शिक्षा का विस्तार लोकतंत्रीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु पहुँच अक्सर वास्तविक सामाजिक गतिशीलता के बजाय असमान परिणामों तक ले जाती है।

कम-मूल्य वाले मार्गों की ओर धकेलना: छात्रों को अक्सर निम्न-स्तरीय विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कॉलेजों में भेज दिया जाता है, जहाँ पाठ्यक्रम कौशल आवश्यकताओं से असंगत होते हैं और रोज़गार संभावनाएँ कमज़ोर रहती हैं।

ग्रे-ज़ोन भर्ती उद्योग: अनियमित भर्ती एजेंसियाँ कानूनी ग्रे-एरिया में कार्य करती हैं और छात्र परिणामों की बजाय कमीशन व मुनाफ़े को प्राथमिकता देती हैं।

लाभ-प्रेरित संस्थागत गठजोड़: भर्ती एजेंसियों और कम-विश्वसनीय निजी कॉलेजों के बीच साझेदारियाँ वैश्विक शिक्षा के व्यावसायीकरण को दर्शाती हैं।

डिस्किलिंग और अल्प-रोज़गार: परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर कौशल-ह्रास होता है, और स्नातकों को कुशल रोज़गार तक पहुँचने में कठिनाई होती है।

छात्र पलायन के संरचनात्मक प्रेरक

- **घरेलू दबाव कारक:** छात्रों का बहिर्वाह देश में प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाता है, जिसमें संस्थानों में कथित गुणवत्ता की कमी और सीमित अच्छी-तनख्वाह वाली रोजगार के अवसर शामिल हैं।
- **केवल शिक्षा की पसंद नहीं:** प्रवासन अकादमिक कारकों से कम और दीर्घकालिक जीवन परिणामों से अधिक प्रेरित है।
- **सस्ते विदेशी विकल्पों का अस्वीकार:** दुबई, सिंगापुर और अन्य जगहों पर पश्चिमी विश्वविद्यालयों के कम लागत वाली डिप्लियाँ प्रदान करने वाले विदेशी परिसरों के बावजूद, भारतीय छात्र शायद ही कभी उनका विकल्प चुनते हैं।
- **संरचनात्मक आकांक्षा अंतर:** ओईसीडी देशों के लिए प्राथमिकता स्थायी निवास, सामाजिक गतिशीलता, और 'तृतीय विश्व' की पहचान से मुक्ति की संभावनाओं से उत्पन्न होती है।
- **श्रम बाजार का विरोधाभास:** छात्र प्रवासन ने ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सस्ते, लचीले श्रमिकों का एक नया समूह उत्पन्न किया है।
- **खाड़ी प्रवासन के समानांतर:** यह खाड़ी श्रम प्रवासन जैसा है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसे घरेलू बचत और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
- **विपरीत रेमिटेंस गतिशीलता:** कमाई घर आने के बजाय, विपरीत रेमिटेंस भारतीय परिवारों से संसाधनों को समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में भेजती है, जिससे वैश्विक असमानताएं और बढ़ती हैं।

अतिरिक्त साक्ष्य और केस स्टडी

- **यूके केस स्टडी:** 1992 के बाद की विश्वविद्यालय (पूर्व पॉलिटेक्निक) अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं, कभी-कभी प्रवेश मानकों में ढील देते हैं, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं।
- **अध्ययन के बाद सीमित गतिशीलता:** कथित तौर पर यूके में हर चार भारतीय स्नातकों में से केवल एक ही प्रायोजित कुशल वीज़ा प्राप्त कर पाता है।
- **जोखिम भरी मध्यम वर्गीय आकांक्षा:** भारत से छात्रों का पलायन मध्यम वर्गीय महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, लेकिन इसमें उच्च वित्तीय और करियर जोखिम शामिल हैं।
- **केरल की बदलती पलायन प्रोफ़ाइल:** केएमएस 2023 के अनुसार, केरल से छात्रों का पलायन पांच वर्षों में दोगुना हो गया (2018 में 1.29 लाख से बढ़कर 2023 में 2.5 लाख), जो कुल प्रवासियों का 11.3% है।
- **रेमिटेंस के तर्क में उलटफेर:** केरल से बाहर जाने वाले छात्रों का रेमिटेंस (₹43,378 करोड़) आने वाले श्रमिक रेमिटेंस के लगभग 20% के बराबर है, जो प्रवासन अर्थशास्त्र में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है।

छात्र प्रवासन में वित्तीय बोझ और रिवर्स रेमिटेंस

- **कर्ज-पूँजीकृत प्रवासन मार्ग:** अधिकांश छात्र उच्च वेतन और बढ़ती गतिशीलता की उम्मीदों से प्रेरित होकर, आत्म-वित्तपोषण या शिक्षा ऋण पर निर्भर करते हैं, और अक्सर पारिवारिक संपत्ति गिरवी रख देते हैं।
- **गतिशीलता का टूटा हुआ वादा:** कई लोगों के लिए, प्रवासन बेहतर आजीविका के बजाय ऋण के जाल, अल्प-रोजगार, या जबरन वापसी का कारण बनता है।
- **रिवर्स रेमिटेंस:** अर्थशास्त्री इस परिणाम को रिवर्स रेमिटेंस के रूप में वर्णित करते हैं, जहाँ भारतीय परिवारों को धन की प्राप्ति के बजाय विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को सब्सिडी मिलती है।
- **मेज़बान अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान:** अंतरराष्ट्रीय छात्र गंतव्य देशों के लिए पर्याप्त आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं।

- **विद्यार्थियों पर कनाडा की निर्भरता:** 2022 में, विदेशी छात्रों ने जीडीपी में \$30.9 बिलियन का योगदान दिया और 3.61 लाख नौकरियों का समर्थन किया; 2023 में, भारतीय छात्रों (4.27 लाख) ने कुल अंतरराष्ट्रीय नामांकन का ~45% हिस्सा बनाया।
- **अमेरिका का मामला:** लगभग 4 लाख भारतीय छात्रों (2024) ने व्यूशन, आवास और रहने की लागतों पर सालाना 7-8 अरब डॉलर खर्च किए, जिससे विश्वविद्यालयों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा मिला।
- **विदेश में शिक्षा की उच्च लागत:** छात्र अक्सर विदेश में पढ़ाई करने के लिए ₹40-50 लाख खर्च करते हैं, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय तनाव पैदा होता है।
- **बढ़ते जीवन यापन का दबाव:** ऊँचे किराए, काम के सीमित धंटे, और वीज़ा सीमाएँ वित्तीय और मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं।
- **पेशेवर गतिशीलता में गिरावट:** कुशल नौकरियों की अनुपस्थिति में, कई छात्र कम वेतन वाले, अनकुशल काम करते हैं, कई अंशकालिक नौकरियों के बीच तालमेल बिठाते हैं, कभी-कभी बिना दस्तावेज़ के, और शोषण का सामना करते हैं।
- **संरचनात्मक बाधाएँ:** प्रतिबंधात्मक वीज़ा व्यवस्था, अध्ययन के बाद काम के सीमित विकल्प, और निम्न-श्रेणी के कॉलेजों से खराब प्लेसमेंट सहायता भेद्यता को और गहरा करती हैं।
- **जीविका के रास्ते बंद होना:** यूके का पिछला विकल्प (2024 से पहले) छात्र वीज़ा से केयर वीज़ा में बदलने का अस्थायी राहत प्रदान करता था, लेकिन नए प्रतिबंधों ने इस रास्ते को समाप्त कर दिया है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है।

निष्कर्ष

भारतीय छात्रों के प्रवासन में यह तीव्र वृद्धि आकांक्षा और वास्तविक परिणामों के बीच, और वादे किए गए अवसरों और वास्तविक शोषण के बीच तीव्र विरोधाभासों को दर्शाती है, जिससे 'ब्रेन गेन' (प्रतिभा का आगमन) के बजाय 'ब्रेन वेस्ट' (प्रतिभा का अपव्यय) पैदा हो रहा है। यह शिक्षा एजेंटों के सरक्त नियमन, प्रस्थान से पहले मजबूत परामर्श, और विदेशी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा छात्र हितों की रक्षा करने के लिए द्विपक्षीय नियामक ढाँचों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है।



Date : 18-12-2025

Gulf of Oman

Syllabus: GS2/ International Relation; GS1/ Places

In News

- Iran seizes foreign oil tanker carrying 6 million litres of smuggled Diesel in the Gulf of Oman.



About Gulf of Oman

- The Gulf of Oman is the north-western arm of the Arabian Sea.
- It forms a vital maritime corridor connecting the Indian Ocean with the Persian Gulf through the Strait of Hormuz.
- Through the Strait of Hormuz, it provides access to the Persian Gulf, making it vital for global oil and LNG trade.
- The Gulf of Oman is bordered by Iran to the north, Pakistan to the northeast, Oman to the south, and the United Arab Emirates (UAE) to the west.

AH-64E Apache Attack Helicopters

Syllabus: GS3/Defence

In news

- The Indian Army received the final batch of three AH-64E Apache attack helicopters.

About

- The Apaches were contracted in 2020 under a \$600 million deal with the United States.
- The AH-64E Apache is regarded as the world's most advanced multi-role combat helicopter.
- It is equipped with cutting-edge avionics, sensors and weapon systems, and capable of operating in all weather and terrain conditions.



The changing patterns of India's student migration

Context

- It reveals gaps between aspiration and outcome, and between opportunity and exploitation.

Introduction

India's latest wave of student migration represents a decisive shift. It is no longer limited to elite universities or fully funded programmes. Instead, contemporary migration is driven largely by self-financed education, with middle-class households making substantial investments in the promise of a global degree, enhanced employability, and upward social mobility.

- Ministry of External Affairs data shows that over 13.2 lakh Indian students were studying across 70+ countries in 2023
- This figure increased to 13.35 lakh in 2024 and is projected to reach 13.8 lakh by 2025
- India ranks among the largest senders of international students globally
- The United States and Canada together account for nearly 40% of Indian student destinations
- Other major destinations include the United Kingdom, Australia, and Germany
- This trend is officially acknowledged in the Parliamentary Committee on the Welfare of Indian Diaspora (2022)
- The Committee identifies students as a key category within India's expanding diaspora

Limits of the 'Democratisation' of Foreign Education

- **Apparent inclusion, deeper inequality:** Expansion of overseas education is projected as democratisation, but access often leads to unequal outcomes rather than genuine mobility.

- **Channelling into low-value pathways:** Students are frequently pushed into lower-tier universities and vocational colleges, with courses misaligned with skills and weak employment prospects.
- **Grey-zone recruitment industry:** Unregulated recruitment agencies operate in a legal grey area, prioritising commissions and profit over student outcomes.
- **Profit-driven institutional linkages:** Partnerships between recruiters and less credible private colleges reflect the commercialisation of global education.
- **Deskilling and underemployment:** The result is widespread deskilling, with graduates struggling to access skilled employment.

Structural Drivers of Student Outmigration

- **Domestic push factors:** Student outflow reflects systemic constraints at home, including perceived quality gaps in institutions and limited well-paid employment opportunities.
- **Not merely an education choice:** Migration is driven less by academic factors and more by long-term life outcomes.
- **Rejection of cheaper offshore options:** Despite Western universities' offshore campuses in Dubai, Singapore, and elsewhere offering lower-cost degrees, Indian students seldom opt for them.
- **Structural aspiration gap:** Preference for OECD countries stems from prospects of permanent residency, social mobility, and an escape from a 'third world' identity.
- **Labour market paradox:** Student migration has generated a new pool of cheap, flexible labour for OECD economies.
- **Parallel with Gulf migration:** This resembles Gulf labour migration, but differs in being financed through household savings and debt.
- **Reverse remittance dynamic:** Instead of earnings flowing home, reverse remittances channel resources from Indian families to rich economies, reinforcing global inequalities.

Additional Evidence and Case Studies

- **UK case study:** Post-1992 universities (former polytechnics) increasingly rely on international students, sometimes relaxing entry standards, raising concerns about academic quality.
- **Limited post-study mobility:** Only one in four Indian postgraduates in the UK reportedly secures a sponsored skilled visa.
- **Risk-laden middle-class aspiration:** Student migration from India reflects middle-class ambition, but entails high financial and career risks.
- **Kerala's shifting migration profile:** As per KMS 2023, student migration from Kerala doubled in five years (1.29 lakh in 2018 to 2.5 lakh in 2023), forming 11.3% of total emigrants.
- **Reversal of remittance logic:** Outward student remittances from Kerala (₹43,378 crore) equal ~20% of inward labour remittances, signalling a structural shift in migration economics.

Financial Burdens and Reverse Remittances in Student Migration

- **Debt-funded migration pathways:** Most students rely on self-financing or education loans, often mortgaging family property, driven by expectations of higher wages and upward mobility.
- **Broken mobility promise:** For many, migration results in debt traps, underemployment, or forced return, rather than improved livelihoods.
- **Reverse remittances:** Economists describe this outcome as reverse remittances, where Indian households subsidise foreign economies instead of receiving inflows.
- **Major contribution to host economies:** International students generate substantial economic value for destination countries.
- **Canada's dependence on students:** In 2022, foreign students contributed \$30.9 billion to GDP and supported 3.61 lakh jobs; in 2023, Indian students (4.27 lakh) made up ~45% of total international enrolments.
- **U.S. case:** Around 4 lakh Indian students (2024) spent \$7–8 billion annually on tuition, housing, and living costs, sustaining universities and local economies.
- **High cost of overseas education:** Students often spend ₹40–50 lakh to study abroad, creating long-term financial stress.
- **Rising living pressures:** High rents, restricted work hours, and visa caps intensify financial and mental strain.
- **Downward occupational mobility:** In the absence of skilled jobs, many students take up low-wage, unskilled work, juggling multiple part-time jobs, sometimes undocumented, and facing exploitation.
- **Structural constraints:** Restrictive visa regimes, limited post-study work options, and poor placement support from low-ranked colleges deepen vulnerability.
- **Closing of survival pathways:** The UK's earlier option (pre-2024) to shift from student visas to care visas offered temporary relief, but new restrictions have eliminated this route, worsening precarity.

Conclusion

This rapid growth in Indian student migration reveals sharp contradictions between aspiration and actual outcomes, and between promised opportunity and lived exploitation, producing what can be termed brain waste rather than brain gain. It underscores the urgent need for stricter regulation of education agents, robust pre-departure counselling, and bilateral regulatory frameworks to ensure accountability of foreign institutions and protect student interests.